Online at: https://researchtrendsjournal.com **ISSN No:** 2584-282X

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 1; Issue 1; 2023; Page No. 390-393

Received: 01-08-2023
Accepted: 06-10-2023

बुनियादी ढांचे के संबंध में कामरूप जिले के प्रांतीयकृत प्राथमिक विद्यालय और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बारपेटा जिले के मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन

[1]दिलीप कुमार, [2]डॉ. महीप कुमार मिश्रा

[1]रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
[2]प्रोफेसर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: दिलीप कुमार

सारांश
प्रत्येक जिले के इन 100 स्कूलों में 50 प्रांतीयकृत और 50 मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए हैं। दोनों जिलों से नमूना स्कूलों की कुल संख्या 200 है। अध्ययन की समस्या, सैद्धांतिक रूपरेखा, उपकरण, नमूने का चयन, डिजाइन और अध्ययन आयोजित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। वर्तमान अध्याय में परिणामों, उनकी व्याख्या और चर्चा पर चर्चा की गई है। इस संदर्भ में, सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता प्राप्त करने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है, यह जीवन में संघर्ष के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण और जीवन कौशल, जीवन जीने की कला के साथ-साथ नए विचारों और दृष्टिकोणों को शामिल करने का पाठ पढ़ा सकती है। जो लोग पारंपरिक मान्यताओं और अंधविश्वासों के साथ रहते हैं, जिनके लिए उनके संपूर्ण मानवीय मूल्यों पर अत्याचार किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, उन्हें शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है जो कि हल्के विचारों का माध्यम है। जनता का अधिकांश पिछड़ापन और गरीबी अशिक्षा और अज्ञानता के कारण है जो शिक्षा की कमी का परिणाम है।

मुख्य शब्दः चयन, डिजाइन, सामाजिक, गतिशीलता, परिवर्तन, शिक्षा

1. प्रस्तावना

शिक्षा विकास का यथोचित अच्छा संकेत है और प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षा का अधिकार मानव अधिकारों पर व्यक्तिगत घोषणा के पहले प्रावधानों में से एक है। भारत का संविधान सभी क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार ने अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से इसका समर्थन किया है, हमारे देश से साक्षरता को खत्म करने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू होने के बावजूद, पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर अभी भी कायम है। भारत का संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे के साथ शिक्षा विषय। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली चार प्रकार की थी। वह है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।

भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और 1986 में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई जिसने शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान की। नीति प्रस्ताव में कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय सेवा और विकास के लिए प्रतिबद्ध चरित्रवान और क्षमता वाले युवा पुरुषों और महिलाओं को तैयार करना चाहिए। निम्नलिखित लक्ष्य हैं; राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, शिक्षा के अवसर को समान बनाना, शिक्षा के मानक का महत्व, शिक्षा को उत्पादकता और राष्ट्रीय विकास से जोड़ना, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना आदि।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1996) ने पहचान की कि प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थिति सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंधकारमय थी। प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए इस नीति में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओबी), प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सिफारिश की गई थी। भारत सरकार ने 2000 में पूरे देश में प्रारंभिक स्तर के लिए एक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम लागू किया। यह कार्यक्रम था सर्व शिक्षा अभियान. "सभी के लिए शिक्षा" इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। सर्व शिक्षा अभियान एक मिशन मोड में पूरे देश को कवर करते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यूईई) को पूरा करने के लिए भारत सरकार का एक व्यापक और एकीकृत प्रमुख कार्यक्रम था। यह सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार का अवसर प्रदान करने का भी एक प्रयास है।

2. साहित्य की समीक्षा

सतविंदरपाल (2012)"प्रारंभिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या: पंजाब के चयनित जिलों का एक अध्ययन" पर एक अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य स्कूल छोड़ने के मुख्य कारणों की पहचान करना था। यह अध्ययन पंजाब में किया गया। नमूने में स्कूल न जाने वाले 150 बच्चे शामिल थे जिनमें से 65 लड़कों और 85 लड़कियों को चुना गया था। अध्ययन के नतीजे से पता चला कि स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण गरीबी, कम उम्र में शादी, अस्वस्थ घर का माहौल, श्रम कार्य में व्यस्तता, अनुपयुक्त स्कूल का माहौल, घर से स्कूल की लंबी दूरी, घरेलू कामों में प्रतिबद्धता, नौकरी के अवसरों की अनुपलब्धता आदि थे। अध्ययन से पता चला कि एसएसए नामांकन दर बढ़ाने में सक्षम था लेकिन ड्रॉपआउट और प्रतिधारण की बाधा को संभाल नहीं सका। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि शैक्षिक नीति को स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के साथ-साथ स्कूलों में ठहराव दर को बढ़ाने के लिए बच्चों की जीवन स्थितियों पर विचार करना चाहिए।

वागले (2012)नेपाल में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर एक अध्ययन किया गया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाना था। यह डेटा संग्रह के गुणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित था जिसमें शिक्षकों और मुख्य शिक्षकों के साथ-साथ बच्चों के साथ अवलोकन, व्यक्तिगत साक्षात्कार और फोकस समूह साक्षात्कार शामिल है। अध्ययन के नमूने में 20 बच्चे, 10 लड़के और 10 लड़कियां, 6 शिक्षक और मुख्य शिक्षक शामिल थे। अध्ययन के परिणाम से पता चला कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण परिवार की कम आय, गरीबी, बाल श्रम और बाल विवाह थे। इसके अलावा, स्कूल से संबंधित मुद्दे जैसे खराब ढांचागत संसाधन, शारीरिक दंड, परीक्षा में असफल होना, सीखने-सिखाने के व्यवहार का अभाव, स्कूली शिक्षा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च स्कूल छोड़ने के महत्वपूर्ण कारण थे। अध्ययन में माना गया कि स्कूल न जाने के कारण बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के परिणामों से गुजरना पड़ता है। सिगरेट पीना, शराब का सेवन और समाज में बहिष्कार की भावना भी देखी गई। यह अनुशंसा की जाती है कि ड्रॉप-आउट की समस्याओं को कम करने के लिए, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के संचालन और राशि में वृद्धि, स्कूलों में भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास, बच्चों के अनुकूल शिक्षण गतिविधियों और ग्रेड के स्वचालित उन्नयन जैसी विभिन्न भागीदारी की जानी चाहिए। इसके अलावा स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को फिर से शुरू करना स्कूलों में ड्रॉप-आउट दर की समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है।

किपकोसगेई (2013)प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा में विकलांग शिक्षार्थियों के नामांकन को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन केन्या के नंदी दक्षिण जिले में किया गया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को समायोजित करने के लिए भौतिक सुविधाओं को कैसे संरचित किया गया था: शिक्षण और सीखने के संसाधनों की पर्याप्तता निर्धारित करना: विशेष शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की पर्याप्तता निर्धारित करना। 44 प्रधानाध्यापकों और 306 कक्षा शिक्षकों पर एक नमूना सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के नतीजे में बताया गया कि अधिकांश (70%) शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के संसाधनों को सीखने की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त पाया। अधिकांश स्कूलों में स्टाफरूम, कक्षा, डेस्क आदि जैसी असंगठित और अपर्याप्त सुविधाएं थीं। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सभी विकलांग शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का विश्लेषण और अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। सरकार को शिक्षकों के लिए संबंधित कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है। नंदी दक्षिण जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कम नामांकन के लिए जिम्मेदार मुख्य विशेषताएं पर्याप्त संरचित सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों, सीखने के संसाधनों, पर्याप्त धन की अनुपस्थिति और अनुपयुक्त पाठ्यक्रम की अनुपस्थिति थीं। यह सुझाव दिया गया कि सीखने की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए।

3. कार्यप्रणाली

एक नमूना अवलोकन और विश्लेषण के लिए चुनी गई जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा है। यह जनसंख्या की वस्तुओं या व्यक्तियों के एक भाग या उपसमूह से बना एक संग्रह है जिसे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए चुना जाता है। वर्तमान अध्ययन के लिए, साक्षरता के आधार पर प्रत्येक जिले से कुल 100 नमूना स्कूलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है (यानी कामरूप जिले से 100 स्कूल और बारपेटा जिले से 100 स्कूल)। प्रत्येक जिले के इन 100 स्कूलों में 50 प्रांतीयकृत और 50 मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए हैं। दोनों जिलों से नमूना स्कूलों की कुल संख्या का डेटा प्रधानाध्यापकों, सहायक शिक्षकों और अभिभावकों से एकत्र किया गया है दूसरे चरण में, अन्वेषक ने कामरूप से 100 प्राथमिक विद्यालयों (50 प्रांतीयकृत और 50 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों से मिलकर) और बारपेटा जिले से 100 प्राथमिक विद्यालयों (50 प्रांतीयकृत और 50 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों से मिलकर) का चयन किया, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से। असम के दोनों जिलों की. 50 प्रांतीयकृत स्कूलों में से 25 शहरी और 25 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का चयन किया गया और दोनों जिलों के मामले में स्कूलों के चयन में समान प्रक्रिया का पालन किया गया। साथ ही, 50 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से शहरी क्षेत्र के 25 और ग्रामीण क्षेत्र के 25 विद्यालयों का चयन किया गया और दोनों जिलों के विद्यालयों के चयन में एक ही प्रक्रिया देखी गई। तीसरे चरण में, अन्वेषक ने 800 उत्तरदाताओं का चयन किया, जबकि प्रत्येक जिले के 400 उत्तरदाता प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक (जिनके पास स्कूलों में न्यूनतम 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव था) और अभिभावक थे जो स्कूल की गतिविधियों से निकटता से जुड़े थे और स्कूल के रिकॉर्ड जानते थे। पिछले 10 वर्षों से. कामरूप जिले में, 400 उत्तरदाताओं में से, चयनित नमूना स्कूलों से प्रधानाध्यापक 100, सहायक शिक्षक 100 और अभिभावक 200 थे। प्रधानाध्यापकों के अनुसार अधिकांश अभिभावक गरीब, मजदूर वर्ग के तथा दैनिक कार्यों में व्यस्त थे तथा जांचकर्ता से बातचीत करने के इच्छुक नहीं थे। अत: प्रधानाध्यापकों के सुझाव के अनुसार एक नमूना विद्यालय से दो अभिभावकों को लिया गया। बारपेटा जिले में भी, 400 उत्तरदाताओं में से, प्रधानाध्यापक 100 थे, सहायक शिक्षक 100 थे और अभिभावक 200 नमूना स्कूलों से थे, जहां अध्ययन का डिज़ाइन निम्नलिखित तालिका में परिलक्षित होता है।

जानकारी प्रधानाध्यापकों, सहायक शिक्षकों और अभिभावकों से दोनों अवधियों के लिए एकत्र की गई थी - सर्व शिक्षा अभियान (बीएसएसए) के कार्यान्वयन से पहले पांच वर्षों के लिए (1996 - 2000 तक) और सर्व शिक्षा अभियान (एएसएसए) के कार्यान्वयन के बाद पांच वर्षों के लिए (से)। 2006 – 2010). एएसएसए की

अवधि के लिए, 2001 से 2005 तक की अवधि को इस अध्ययन में नहीं लिया गया, क्योंकि इस अवधि के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान ने असम के जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विभिन्न केंद्रों और समितियों का गठन ठीक से नहीं किया था। योजना। इसलिए, एसएसए द्वारा दोनों जिलों में प्राथमिक शिक्षा की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए इस अध्ययन के लिए एएसएसए के लिए 2006 से 2010 तक की अवधि पर विचार किया गया था। सांख्यिकीय उपचार के लिए, दोनों अवधियों (एसएसए से पहले और एसएसए के बाद) के लिए दो जिलों के बीच प्राथमिक शिक्षा पर एसएसए के प्रभावों का पता लगाने के लिए सरल प्रतिशत (गैरेट, 1966 का उपयोग किया गया) का उपयोग किया गया था। वर्तमान अध्ययन के इतने विशाल क्षेत्र के परिणाम प्राप्त करने के लिए सरल प्रतिशत तकनीक का उपयोग किया गया।

4. डेटा विश्लेषण और व्याख्या

तालिका 1: बुनियादी ढांचे के संबंध में कामरूप जिले के प्रांतीयकृत प्राथमिक विद्यालय और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बारपेटा जिले के मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय

वस्तु	कामरूप								बारपेटा								कामरूप								बारपेटा							
	प्रांत. प्राथमिक स्कूल								पहचान. प्राथमिक स्कूल								प्रांत. प्राथमिक स्कूल								पहचान. प्राथमिक स्कूल							
	मुखिया		सहायक टी.सी.आर		संरक्षक		मुखिया		सहायक टी.सी.आर		संरक्षक		मुखिया		सहायक टी.सी.आर		संरक्षक		मुखिया		सहायक टी.सी.आर		मुखिया									
	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %	यू %	आर %
वित्त	35	25	25	20	24	16	15	09	10	06	12	09	85	70	80	65	80	65	75	60	68	55	65	50								
एससीएल.कार्यालय	37	30	30	17	20	15	20	10	12	08	15	08	80	72	85	68	75	62	60	20	55	18	50	20								
सीएल.रूम	35	28	25	20	39	30	15	09	10	05	22	16	82	75	85	70	75	65	70	50	64	54	60	48								
लिब सुविधा	14	07	10	06	08	07	10	04	06	02	06	04	24	08	20	05	12	07	15	06	12	08	10	05								
टीसी .कक्ष	28	20	14	08	08	13	10	06	08	04	05	02	61	55	51	50	50	30	50	18	44	20	40	15								
डी .पानी	42	24	38	20	40	30	30	10	25	10	35	15	85	70	86	65	85	76	70	60	67	60	65	50								
टी.शौचालय	40	32	35	25	40	46	20	08	11	07	10	05	77	68	81	63	75	60	40	20	30	20	47	15								
पी. शौचालय	44	35	37	22	45	50	23	12	16	10	25	18	85	75	78	70	85	72	65	50	60	52	60	47								
पी.एल.ग्राउंड	45	36	38	40	50	44	32	17	22	13	25	15	55	60	50	65	60	75	40	40	37	45	47	40								
एस.व्यवस्था	40	32	30	18	38	32	14	14	23	07	25	11	80	74	83	70	86	73	52	47	58	52	58	42								

तालिका से पता चलता है कि प्रांतीयकृत प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं को वित्त, स्कूल कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, शिक्षकों के सामान्य कक्ष, पीने के पानी, शिक्षकों के शौचालय, विद्यार्थियों के शौचालय, खेल के मैदान और बैठने की व्यवस्था के क्षेत्रों में दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से पहले प्रधानाध्यापकों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार कामरूप जिले के शहरी क्षेत्र में क्रमशः 35%, 37%, 35%, 14%, 28%, 42%, 40%, 44%, 45% और 40% थे। , जबकि सर्व शिक्षा अभियान के बाद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का परिणाम क्रमशः - 85%, 80%, 82%, 24%, 61%, 85%, 77%, 85%, 55% और 80% पाया गया।

फिर से, यह देखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से पहले प्रांतीयकृत प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं में वित्त, स्कूल कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, शिक्षकों के सामान्य कक्ष, पीने के पानी, शिक्षकों के शौचालय, विद्यार्थियों के शौचालय, के क्षेत्रों को दिखाया गया था। कामरूप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में खेल का मैदान और बैठने की व्यवस्था क्रमशः - 25%, 30% 28%, 07%, 20%, 24%, 32%, 35%, 36% और 32% थी, जबकि बुनियादी सुविधाओं का परिणाम प्रधानाध्यापकों की प्रतिक्रियाओं से सर्व शिक्षा अभियान के बाद क्षेत्र क्रमशः - 70%, 72%, 75%, 08%, 55%, 70%, 68%, 75%, 60% और 74% पाया गया।

इसी तालिका से यह देखा गया है कि मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं को वित्त, स्कूल कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, शिक्षकों के सामान्य कक्ष, पीने के पानी, शिक्षकों के शौचालय, विद्यार्थियों के शौचालय, खेल के मैदान और बैठने की व्यवस्था के क्षेत्रों में दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से पहले प्रधानाध्यापकों की प्रतिक्रिया के अनुसार बारपेटा जिले के शहरी क्षेत्र में क्रमशः 13%, 17%, 12%, 08%, 09%, 15%, 18%, 20%, 32% और 14% थे। जबकि सर्व शिक्षा अभियान के बाद शहरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का परिणाम क्रमश: 70%, 28%, 55%, 12%, 28%, 65%, 45%, 61%, 40% और 52% पाया गया।

5. निष्कर्ष

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास को सुविधाजनक बनाने में मार्गदर्शन करने वाली एक संक्षिप्त चर्चा और सुझाव इस प्रकार हैं:

हम जानते हैं कि शिक्षा समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि हम विश्व के इतिहास पर नजर डालें तो यह प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास का मुख्य कारक रहा है। आज हम जान रहे हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया कई देशों को मानव और सभ्यता के विकास की दिशा में बदल रही है। भारत जैसे देश में जहां सांप्रदायिक अशांति, जनसंख्या में भारी वृद्धि, गरीबी की कमी, विकास प्रक्रिया की दोषपूर्ण योजना जैसे विभिन्न कारणों से विकास प्रक्रिया सीमित है; इसलिए, समाज और दुनिया में मानवता की नींव विकसित करने के लिए शिक्षा को इन बुराइयों के खिलाफ एक उपकरण और चुनौती के रूप में माना जाना चाहिए।

यह सच है कि 21वीं सदी में, सामाजिक वैज्ञानिक मानवता के बजाय धन के साथ अर्थशास्त्र और लोगों के विकास के लिए विभिन्न अवसरों के विस्तार के बजाय आय के अधिकतमकरण के साथ समाज के बारे में अधिक चिंतित हो गए हैं। वास्तविक अर्थ.

सभी ने भौतिकवाद के प्रति जुनून की तलाश की, शायद हाल ही में, अर्थशास्त्रियों, सामाजिक दार्शनिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों, भूगोलवेत्ताओं और नीति निर्माताओं का अधिशेष व्यापार संतुलन में राष्ट्रीय खजाने को बढ़ाने में व्यस्तता, जिन्होंने विकास के बजाय भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया।

6. संदर्भ

1. अरिंदम मेटिया "सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका (ईएफए): जलपाईगुड़ी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का एक अध्ययन", 2018
2. मैरी चांडी वायलीपरमपिल और अन्य "भारत में स्कूल नामांकन बढ़ाने में सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता के हितधारकों की धारणाएँ" 2012.
3. एम. राधिका और डॉ. वी. रेवथी, सर्व शिक्षा सदस्यता (एसएसए) हासिल करने की दिशा में भारत के पथ का आकलन: एक दृश्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट (आईजेएम)। 2020;11(11):4080-4085 डीओआई:https://doi.org/10.17605/OSF.IO/W85QN
4. प्रीति एट अल "सर्व शिक्षा अभियान- भारत में शिक्षा की एक सफल योजना" जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस www.iiste.org ISSN 2222-1735 (पेपर) ISSN 2222-288X (ऑनलाइन), 2015, 6(28).
5. पाहवा, निकिता, महेंद्रवाड़ा, इंदिरा। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का प्रदर्शन मूल्यांकन: भारत में दो राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन। 2021;11:86-98.
6. एक्टर एफ, रहमान ई, रहमान एच, हक ओ. बांग्लादेश में शारीरिक विकलांग बच्चों की शिक्षा में पर्यावरणीय बाधा। ईसी ऑर्थोपेडिक्स, 2019;10(2):01-04. https://www.ecronicon.com>ECOR-w00544.pdf.
7. आलम, एमयू. प्रारंभिक शिक्षा के प्रति बालिकाओं की प्रतिक्रिया: सर्व शिक्षा अभियान मिशन सिलीगुड़ी का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ इंडियन एडल्ट एजुकेशन. 2012;73(04):51-65. Https://northbengal.acadmedia-edu/malam
8. बाला मैं. भारत में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। उन्नत अनुसंधान और विकास के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल. 2017;2(1):13-15. https://www.advancedjournal.com/download/210/2-1-12-156-pdf.
9. बेस्ट, जेडब्ल्यू, काह्न, जेवी. शिक्षा में अनुसंधान. पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।, 2012.
10. बिष्ट ए, पाल के. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत छात्रों की शिक्षा के प्रावधानों का प्रभाव (डॉक्टरेट थीसिस, हिमाचल प्रदेश), 2016. https://shodnga.inflibnet.ac.in/handle/10603/202002.
11. बोरा, एमएफएस, मार्सिवडोरजिरवा एम. ऊपरी शिलांग, पूर्वी खासी पहाड़ी जिला, मेघालय में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान जर्नल, 2018, 4(12). https://doi.org10.21276/24455.295X.
12. ब्रिटानिका टी. एनसाइक्लोपीडिया के संपादक। (2022, 30 मार्च)। बुनियादी तालीम। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। 5 फरवरी, को पुनः प्राप्त किया गया, 2021. https://www/britannica.com/topic/elementaryeducation.
13. चदा ए, दास एसी। 2004-2013 के दौरान त्रिपुरा में सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों और चुनौतियों पर अध्ययन (डॉक्टरेट थीसिस, कल्याणी विश्वविद्यालय), 2017. http://Shodnga.inflibnet.ac.in/handle.net/10603/250740.
14. डेरी डीयू, रेड्डी पीए. शिक्षा तक पहुँचने में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की समस्याएँ; पर्यावरण से बाधा की भूमिका - एक केस अध्ययन। बल्गेरियाई जर्नल ऑफ साइंस एंड एजुकेशन पॉलिसी. 2016;10(1):90-105. 2 फरवरी 2022 को https://bjsep.org/index.php?page=11 से लिया गया

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.